



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, बुधवार, 30 दिसम्बर, 1992/9 पौष, 1914

हिमाचल प्रदेश सरकार

लोकायुक्त कार्यालय
(जांच आयोग)

अधिसूचना

शिमला-171002, 23 दिसम्बर, 1992

संख्या 5 (ई) 5-2/92-लोका० (15-ए).—हिमाचल प्रदेश सरकार को यह सूचित किया गया है कि 21 मार्च, 1992 को ऊना में हुये मैड़ी मेले में श्रद्धालुओं तथा वहां पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैनात पुलिस बल में झड़प हुई थी ;

और यह प्रारोप लगाया गया है कि पुलिस बल ने अभिकथित रूप में अपने प्राधिकार का दुरुपयोग किया, श्रद्धालुओं को पिटाई की और अनुचित रूप से धार्मिक स्थान की पवित्रता का प्रतिक्रमण करने का प्रयास किया;

और जिला मैजिस्ट्रेट, ऊना ने इस घटना की सच्चाई जानने के लिए मैजिस्ट्रेटी जांच का आदेश दिया था ;

और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए यह समीचीन होगा कि कि उक्त घटना जो कि महत्वपूर्ण मामला है, की जांच के लिए जांच आयोग नियुक्त किया जाए;

और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल ने इस सरकार की पत्र संख्या गृह (ए) ए (9) 24/92 तारीख 23-9-92 द्वारा माननीय लोकायुक्त, हिमाचल प्रदेश से उपर्युक्त घटना की सचाई जानने के लिए जांच आयोग के रूप में उनकी नियुक्ति के लिए सहमति मांगी थी;

और माननीय लोकायुक्त, हिमाचल प्रदेश के आयुक्त एवं सचिव ने पत्र संख्या 5 (ई) 5-2/92-लोका0 (15-ए) दिनांक 25 सितम्बर, 1992 द्वारा प्रस्तावित जांच करने के लिए माननीय लोकायुक्त, हिमाचल प्रदेश की सहमति दे दी गई है :

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, जांच आयोग अधिनियम, 1952 की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त अधिनियम, 1983 (1983 का 17) की धारा 15-ए के अधीन, लोकायुक्त, हिमाचल प्रदेश के परामर्श से राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण) तारीख 18-7-92 में प्रकाशित इस सरकार की अधिसूचना संख्या गृह (ए) ए (9) 24/92 तारीख 17 जुलाई, 1992 का अधिकरण करते हुए लोकायुक्त हिमाचल प्रदेश को उपर्युक्त घटना से सम्बन्धित निम्नलिखित विषयों पर जांच करने और इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छः मास की अवधि के भीतर इस निमित्त अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत करने के लिए नियुक्त करते हैं ।

1. घटना स्थल पर, घटित होने से पूर्व और पश्चात् क्या स्थिति थी,
2. क्या तथ्य और परिस्थितियां थी जिनके कारण अभिकथित मारपीट पत्थर फैंकने और आगजनी, हत्यादि की गई और मौके पर तैनात कानून व्यवस्था बनाए रखने वाले तन्त्र की क्या प्रतिक्रियाएं थी और अनुक्रियाएं भी,
3. क्या यह सत्य है कि कुछ पुलिस कर्मियों ने अपने आचरण के विरुद्ध कार्य करते हुए धार्मिक स्थान की पवित्रता का अतिक्रमण किया,
4. क्या यह सत्य है कि वहां पर चल रहे खण्ड पाठ में उन्होंने बिध्न डाला और ग्रंथियों से मारपीट की,
5. यदि कोई सुरक्षा कर्मी धार्मिक स्थान के ग्रन्थी की सुरक्षा हेतु तैनात थे तो उन्होंने क्या भूमिका निभाई ,
6. भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए आवश्यक उपायों की सिफारिश करना, और
7. कोई अन्य विषय जो आयोग की राय में उपर्युक्त घटना के सम्बन्ध में तथ्यों को अभिनिश्चित करने से सुसंगत हो ।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की आगे की यह राय है कि, की जाने वाली जांच की प्रकृति और मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, जांच आयोग अधिनियम, 1952 की धारा 5 की उप-धारा (2), (3), (4) और (5) के उपबन्धों को आयोग के लिए लागू किया जाए और उल्लेखित अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निदेश देते हैं कि धारा 5 की उप-धारा (2), (3), (4) और 5 में उल्लिखित उपबन्ध आयोग को लागू होंगे ।

2. अतः अब यह अधिसूचना लोकायुक्त द्वारा और उनके आदेशानुसार जारी की जाती है कि वह व्यक्ति जो इस जांच से सम्बन्धित विभिन्न अनुच्छेदों में उल्लेखित विचारार्थ विषयों से सम्बन्धित शपथ पत्र (पत्रों) तथा जिस विषय में बयानकर्ता बयान करने में सक्षम हों, ग्रामनिवृत्त करते हैं । ऐसे शपथ पत्र (पत्रों) केवल उन्हीं विषयों तक पूर्णतया सीमित होने चाहिए और तथ्यों का विवरण जो कि शपथ पत्र (पत्रों) में दर्शाता हो , मद्द विषयों से विशेष तौर पर सम्बन्धित होना चाहिए । ऐसे शपथ-पत्र (पत्रों) ठीक ढंग से

निम्नलिखित प्रकार से सत्यापित होने चाहिए, जैसे कि "उपरोक्त शपथ पत्र (पत्रों) में अनुच्छेदों..... में वर्णित विवरण में मेरी जानकारी के मुताबिक सही है" और यदि विवरण प्राप्त सूचना से लिया गया है "कि अनुच्छेदों..... में दिया गया विवरण..... (सूचनादाता का नाम) निवासी... से प्राप्त सूचना पर आधारित है और मैं इसे विश्वस्तः सही मानता हूँ।" यदि सूचना हिमाचल प्रदेश सरकार के किसी कर्मचारी से प्राप्त हो और ब्यानकर्ता उनका नाम शपथ-पत्र (पत्रों) में नहीं दर्शाना चाहता हो तो सत्यापन इस प्रकार होना चाहिए "अनुच्छेदों..... में दिया गया विवरण सरकारी स्त्रोत/स्त्रोतों से लिया गया है।" प्रत्येक मूल शपथ-पत्र (पत्रों) तथा इसकी एक प्रतिलिपि सहित इस अधिसूचना के जारी होने के एक मास के भीतर लोकायुक्त, हिमाचल प्रदेश के कार्यालय "पाईन्ज ग्रीव भवन" शिमला-171 002 में किसी भी कार्य दिवस को सुबह 10 बजे से सायं 5 बजे तक दायर होना चाहिए। यदि शपथ-पत्र (पत्रों) के उपरोक्त ढंग से सत्यापित न किए गए हों या उपरोक्त निर्धारित तिथि व समय के अन्दर दायर न किए जाएं तो उन शपथ-पत्र (पत्रों) पर लोकायुक्त, हिमाचल प्रदेश द्वारा कोई भी विचार नहीं किया जाएगा।

3. जब भी ब्यानकर्ता को बुलाया जाए तो वह लोकायुक्त, हिमाचल प्रदेश के कार्यालय में उपस्थित हों और उसके पास दस्तावेज मौजूद हों और इस जांच से सम्बन्धित अन्य सूचना भी प्रस्तुत करें।

यद्यपि यह अधिसूचना पहले दिनांक 29-10-1992 को सर्वसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित की गई थी परन्तु प्राप्त शपथ-पत्रों की संख्या को देखने से लगता है कि इसकी सूचना व्यापक रूप से जन साधारण तक नहीं पहुंच पाई है। अतः जन साधारण को इसके लिए और अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से माननीय लोकायुक्त महोदय ने आदेश किए हैं कि शपथ-पत्र अब 31 जनवरी, 1993 तक लोकायुक्त, हिमाचल प्रदेश के कार्यालय "पाईन्ज ग्रीव भवन" शिमला-171 002 में किसी भी कार्य दिवस को प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक दायर किए जा सकते हैं।

शपथ-पत्र दायर करने के लिए अन्य शर्तें वही होंगी जो पहले प्रकाशित अधिसूचना समसंख्या दिनांक 29-10-92 में निर्धारित है।

आदेश द्वारा,

राजेन्द्र भट्टाचार्य,
आयुक्त एवं सचिव,
लोकायुक्त एवं जांच आयोग।

OFFICE OF THE LOKAYUKTA

(Commission of Inquiry)

NOTIFICATION

Shimla-171 002, 23rd December, 1992

No. 5(E)5-2/92-Loka(15-A).—Whereas, it has been reported to the Himachal Pradesh Government that a clash between the devotees and the police force deployed for maintenance of law and order at Mairi fair at Una took place on March 21st, 1992;

And whereas, it has been alleged that the police force allegedly abused their authority, beat up the devotees and unduly tried to violate the sanctity of the religious place;

And whereas, the District Magistrate, Una had ordered a Magisterial inquiry to get at the truth behind this incident;

And whereas, the Governor of Himachal Pradesh is of the opinion that it would be more expedient and in the public interest to appoint a Commission of Inquiry to inquire into the aforesaid occurrence which is a matter of importance;

And whereas, the Governor of Himachal Pradesh has approached the Hon'ble Lokayukta, Himachal Pradesh, *vide* this Government letter No. Home (A) A(9)24/92, dated 23rd September, 1992 to have his consent for appointment as the Commission of Inquiry to inquire into the truth behind the aforesaid incident;

And whereas the Commissioner-*cum*-Secretary to Lokayukta, Himachal Pradesh has conveyed the consent of the Hon'ble Lokayukta, Himachal Pradesh for holding the proposed inquiry *vide* letter No. 5(E)5-2/92-Loka(15-A) dated 25th September, 1992;

Now, therefore, in exercise of the powers vested in him under sub-section (1) of section 3 of the Commission of Inquiry Act, 1952, in consultation with the Lokayukta, Himachal Pradesh, under section 15-A of the Himachal Pradesh Lokayukta Act, 1983 (Act No. 17 of 1983) and in supersession of the Government Notification No. Home (A) A(9)24/92, dated the 17th July, 1992, Published in the Rajpatra of Himachal Pradesh (Extra-Ordinary) dated 18th July, 1992, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to appoint the Hon'ble Lokayukta, Himachal Pradesh as the Commission of Inquiry to inquire into and report on the following matters in relation to the aforementioned occurrence within a period of six months from the date of publication of this Notification :—

- (1) what was the situation prevailing on the spot before and after the incident;
- (2) what were the facts and circumstances leading to the alleged beatings, stone throwing and arson etc.? and what were the reasons and responses of the law and order enforcement machinery deployed at site?
- (3) whether it is a fact that some of the police personnel by virtue of their conduct violated the sanctity of the religious place?
- (4) whether it is a fact that they disturbed the recitation of the Akhand Path and beat the Granthis;
- (5) what was the role played by the security guards, if any, attached to the Granthi of the religious place;
- (6) to recommend steps necessary for the prevention of re-occurrence of such incidents in future? and
- (7) any other matter in the opinion of the Commission relevant to the ascertaining of facts relating to the aforesaid occurrence;

Further, the Governor of Himachal Pradesh is of the opinion that having regard to the nature of the inquiry to be conducted and circumstances of the cases the provisions of sub-section (2), (3), (4) and 5 of section 5 of the Commission of Inquiry Act, 1952, should be made applicable to the Commission and in exercise of the powers vested in him under sub-section (1) of Section 5 of the aforesaid Act, is pleased to direct that the provisions mentioned in sub-section (2), (3), (4) and (5) of section 5 shall apply to the Commission.

2. Now, therefore, this notification is issued, by and under the order of the Lokayukta, Himachal Pradesh, inviting all persons acquainted with the subject matter of the inquiry to furnish to the Lokayukta, affidavit(s) containing a statement of facts set out in several paragraphs

relating to terms of reference, mentioned above, as to which the deponent is competent to depose. Such affidavit(s) must be strictly confined to these matters only and the statements of facts to be set forth in the affidavit(s) must be expressed to be related to particular items of reference. Such affidavit(s) must be properly verified in the following manner, namely "That the statement in paragraphs of the fore-going affidavit(s) are true to my knowledge," and in case the statements are derived from the information received "That the statements in paragraphs.....are based on the information received by me from..... (naming the informant) resident of.....and belived by me to be true." If the information has been received from an official from the Government of Himachal Pradesh and the deponent does not desire to disclose his name in the affidavit(s), the verification should be "That statement contained in paragraphs.....are derived from official source/sources." The original affidavit(s) with the duplicate copy of each must be filed within a month from the date of issue of this notification in the office of the Lokayukta, Himachal Pradesh, Pines Grove Building, Shimla-171 002, on any working day between the hours of 10.00 A.M. to 5.00 P.M. Affidavit(s) not verified in the matter indicated above or not filed within the date and time specified above, will not be taken into consideration by the Lokayukta, Himachal Pradesh.

3. Also if and when called upto do so, the deponent should attend the office of the Lokayukta and produce documents which he may have in his possession or furnish any further information regarding the subject matter of inquiry.

4. Though the above Notification was issued for information of general public on 29th October, 1992, but, from the Affidavit(s) received so far, it appears that content of his Notification have not reached the general public. Therefore, the Hon'ble Lokayukta, Himachal Pradesh has ordered that in order to give still more wide publicity to the general public the date of filing of affidavit (s) by the general public is extended upto 31st January, 1993. Other conditions of filing of affidavit(s) shall remain the same as laid down in this Commission's Notification of even number dated the 29th October, 1992.

By order,

RAJENDAR BHATTACHARYA,
Commissioner-cum-Secretary,
Lokayukta-cum-Commission of Inquiry,
Himachal Pradesh.